

ध्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-- खण्ड 3-- उपकाण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई विरुली, शुक्रवार, मई 19, 1972/वैशाख 29, 1894

No. 250]

NEW DELHI, PRIDAY, MAY 19, 1972/VAISAKHA 29, 1894

इस भाग में भिन्न पूष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह ग्रास्थ संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 19th May 1972

S.O. 362(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that M/s. Alagappa Textiles (Cochin) Ltd., Alagappanagar, an industrial undertaking in respect of which an investigation has been made under section 18 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is being managed in a manner highly detrimental to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 18A of the said Act, the Central Government hereby authorises the Kerala Textile Corporation (hereinafter referred to as Authorised Controller) to take over the management of the whole of the said undertaking, namely M/s. Algappa Textiles (Cochin) Ltd., Alagappanagar, subject to the following terms and conditions, namely:—

(i) The Authorised Controller shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government.

(ii) The Authorised Controller shall hold office for five years from the date of publication in the official gazette of this notified order.

(iii) The Central Government may terminate the appointment of the Authorised Controller earlier, if it considers it necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the official gazette.

[No. F. 3(6)/72-CUC.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

ग्रीषोगिक विकास मंत्रालय

(मोद्योगिक विकास विभाग)

घावेश

नई दिल्ली, 19 मई, 1972

का० आ० 362 (आ).—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि मैसर्स प्रलागम्या टैक्सटाइल्स (कोचीन) लि०, प्रलागप्पा नगर नामक श्रौद्योगिक उपक्रम का, जिसके सम्बन्ध में उद्योग (विकास तथा विमियमन) प्रधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के प्रधीन एक जांच की गई है, प्रबन्ध इस ढ़ंग से किया जा रहा है जो सार्वजनिक हित में बहुत ही शहितकर है;

भ्रत भ्रव उपरोक्त प्रधिनियम की धारा 18-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार केरल वस्त्र निगम (इसमें जिसे एतदोपरान्त प्राधिकृत नियंत्रक कहा जाएगा) को मैसर्स प्रलागप्या टैक्सटाईल्स (कोचीन) लि०, भ्रलागप्या नगर नामक उपरोक्त संपूर्ण उपक्रम का प्रवंध भ्रपने श्रधिकार में लेने के लिए, निम्नलिखित शतौं के भ्रष्ट्यधीन एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है, अर्थात् :--

- (1) प्राधिकृत नियंत्रक, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निवेशों का पालन करेगा :
- (2) प्राधिकृत नियंत्रक इस अधिसूचित आदेश के सरकारी राजपल में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए वद धारण करेगा;
- (3) केन्द्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना भावश्यक समझेगी तो उससे पूर्व भी इस प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति को समाप्त कर सकती है।
- 2. यह भ्रादेश सरकारी राजपन्न में इसके प्रकासित होने की तारीख से भारम्भ होने वाली पांच वर्ष की भ्रवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

[सं॰ फ॰ 3(6)/72-सी॰यू॰सी॰] एस॰ के॰ सहगल, संयुक्त सचिव।